प्राकृतिक गैस के व्यर्थ रिसाव को रोकने के संबंध में परियोजना

*733. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

श्री राम जेठमलानी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस के व्यर्थ रिसाव को रोकने के लिये परियोजना तैयार की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस परियोजना के निर्माण के बाद देश में प्राकृतिक गैस का रिसाव पूर्ण रूप से रुक जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के निर्माण पर कुल कितनी राशि व्यय होने की संभावना है ; और

(घ) सरकार ने इस राशि को प्राप्त करने के लिये किन-किन वित्तीय संस्थाओं से आग्रह किया है और इस संबंध में अभी तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) से (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इंडिया लिमिटेड ने पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, गुजरात, असम आदि में संबद्ध गैस के दहन को रोकने के लिए अनेक ऐसी परियोजनाएं हाथ में ली हैं जिसके पूरा होते ही दहन के न्यूनतम तकनीकी अपेक्षाओं तक घट जाने की आशा की जाती है । इस परियोजना पर लगभग 10,000 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है ।

(घ) विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक और जापान के एक्जिम बैंक ने क्रमशः 450 मिलियन, 300 मिलियन और 181 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण अनुमोदित कर दिये हैं ।

Modification in Dock Workers, Act, 1948

*234. SHRI V. RAJESHWAR RAO:
DR. SHRIKANT RAM CHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) what is the total number of Dock workers in the country, State-wise; and

(b) whether Government contemplates any modification in the Dock Workers Act, 1948?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) The number of Dock Workers Dock Labour Board-wise is as under:—

S. No.	Dock Labour Board	No. of workers
1	Kandla	955
2	Cochin	599
3	Madras	2175
4	Visakhapatnam	1928
5	Bombay	7123
6	Calcutta	4084
7	Mormugao	887
	TOTAL	17,751

(b) No such proposal is under consideration.